हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 02 | अंक : 60 | जौनपुर, शनिवार 25 नवम्बर 2023 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य : 2 रूपया

टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर मोदी बेहद संवेदनशील

एजेन्सी

देहरादून/उत्तरकाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर भी बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टनल से बाहर आने पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल या घर भेजने की व्यवस्था के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री मोदी रोजाना सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों एवं उनके परिजनों के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को फोन कर अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी से बातचीत में शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने बचाव कार्य में उत्पन्न होने वाली बाधा और रुकावट के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड से इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस्पात से बनी वस्तुओं के ऑगर मशीन के सामने आने पर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे

में ऑगर मशीन को रोककर और फिर उसे बाहर निकालकर सभी अवरोधों को श्रमिकों द्वारा दूर किया जा रहा है, जिसके कारण इस प्रक्रिया में समय लग रहा है। मुख्यमंत्री को इस दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष निर्देश दिए कि जब श्रमिक टनल से बाहर निकलेंगे तो उनके स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सकीय देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सुरंग के अंदर फँसे श्रमिकों की स्थिति और उनको दी जाने वाली खाद्य और दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं के बारे में जानकारी लेने के साथ ही राहत तथा बचाव कार्य में लगे श्रमिकों की स्थिति एवं उनके लिए किए जा रहे सुरक्षा के उपाय के बारे में पूछा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें किसी तरह की कोई कमी न रहे। उन्होंने बचाव कार्य की प्रगति और किए जा रहे कार्यों के साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और यदि किसी अन्य सहयोग की जरूरत है तो उस पर जानकारी ली। साथ ही श्रमिकों के परिजनो के बारे में जानकारी भी ली। श्री धामी ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही उनके द्वारा मातली उत्तरकाशी में ही अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थापित किया है ताकि बेहतर ढंग से पूरे ऑपेरशन की मॉनिटरिंग हो सके। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि छह इंच व्यास के पाइप लाइन मलवे के सफलता पूर्वक बिछाए जाने के बाद वैकल्पिक लाइफ लाइन बनाई गई है। जिसके माध्यम से टनल में फंसे श्रमिकों तक ताजा पका भोजन, फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, जूस के साथ ही डिसपोजेबल प्लेट्स, ब्रश, तौलिया, छोटे कपड़े, टूथ पेस्ट, साबुन, आदि दैनिक आवश्कता की सामग्री बोतलों में पैक कर भेजी जा रही है। जिससे श्रमिकों के भोजन एवं पोषण की समस्या को लेकर अब कोई चिंता नहीं है। इसी पाइप लाइन के जरिए एसडीआरएफ द्वारा स्थापित कम्युनिकेशन सेटअप के माध्यम से श्रमिकों से नियमित संवाद किया जा रहा है। इसी माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवार जनों को भी बातचीत कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं भी इसी माध्यम से श्रमिकों का हाल–चाल जाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रमिको एवं उनके परिजनों का मनोबल बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सिलक्यारा में स्थापित अस्थाई अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स के द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ के निरंतर निगरानी की जा रही है। एम्बुलेंस से लेकर नजदीकी अस्पताल में 41 विशेष बेड श्रमिकों हेतु तैयार किये गए हैं। मनोचिकित्साको के द्वारा भी नियमित रूप से टनल में फंसे श्रमिकों की काउंसलिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राहत और बचाव कार्यों में जुटे श्रमिक पूरे पूरे मनोयेाग एवं अथक परिश्रम से जुटे हुए हैं। इन श्रमिकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सुपोषित और स्वस्थ बच्चे ही सशक्त भारत का आधार बनेंगे : योगी

एजेन्सी

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में तीन से छह वर्ष के बच्चों को मध्याह्न भोजन (मिड–डे मील) की तर्ज पर पका हुआ गर्म भोजन परोसने की शुरुआत करते हुए कहा कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे ही सशक्त भारत का आधार बनेंगे। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शुक्रवार को अयोध्या पुलिस लाइन स्थित कंपोजिट विद्यालय से 'हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत करते हुए योगी ने कहा कि रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रदेश में तीन से छह साल के बच्चों को 'मिड–डे मील की तर्ज पर बना हुआ गर्म भोजन परोसने के कार्य की शुरुआत अयोध्या से होना अत्यंत ही शुभ कार्य है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 403 करोड़ की लागत से 35 जिलों में 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। साथ ही अयोध्या रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मिड–डे मील की तर्ज पर बना हुआ गर्म भोजन अलग–अलग व्यंजन सूची (मेन्यू) के आधार पर अलग–अलग दिन परोसने की ये योजना विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ेगी। योगी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस का उदाहरण देते हुए कहा कि अंतरविभागीय समन्वय के चलते जो बीमारी 40 साल में 50 हजार बच्चों को निगल गई उसे हमने चार साल में नियंत्रित कर लिया। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि अंतरविभागीय समन्वय से योजनाओं पर कार्य हो तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार प्रदेश में तीन से छह साल के 80 लाख बच्चों को 'पका हुआ गर्म भोजन प्रदान करने के कार्य की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में पाला था, मगर आप सैकड़ों कान्हाओं की सेवा करने, उनके पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में भाजपा की मेगा रैली को दी अनुमति

एजेन्सी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को भाजपा को शहर में उसी स्थान पर 29 नवंबर को अपनी मेगा रैली करने की अनुमति दे दी, जहां राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को अपनी वार्षिक शहीद दिवस रैली आयोजित करती है। पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत 100 दिन की नौकरी योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के विरोध में आयोजित होने वाली भाजपा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ–साथ केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और निरंजन ज्योति के भी शामिल होने की उम्मीद है। सोमवार को, न्यायमूर्ति राजशेखर मंटा की एकल–न्यायाधीश की पीठ ने रैली के लिए पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने पर भाजपा को पसंद के स्थान पर इसे आयोजित करने की अनुमति दी थी। लेकिन बुधवार को, राज्य सरकार ने एकल–न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ से संपर्क किया। खंडपीठ ने शुक्रवार को भी एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा और भाजपा को अपने कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसमें यह भी कहा गया कि हालांकि भाजपा को कोलकाता पुलिस की शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार रैली आयोजित करनी होगी, लेकिन बाद में आयोजकों पर कोई अतिरिक्त या नया प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत की टिप्पणी यह थी कि यदि कोई विशेष कार्यक्रम (तृणमूल कांग्रेस की ष्शहीद दिवसष् रैली पढ़ें) मध्य कोलकाता में उस स्थान पर आयोजित किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि किसी अन्य आयोजक द्वारा उसी स्थान पर एक समान रैली का आयोजन नहीं किया जा सकता है।

भारत–नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ़ में शुरू

एजेन्सी

पिथौरागढ़। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण में भाग लेने के लिए 334 कर्मियों वाली नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची है। यह अभ्यास आज से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और दोनों देशों में आयोजित किया जाता है।

354 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। नेपाल सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व तारा दल बटालियन द्वारा किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध,पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर–संचालनीयता को बढ़ाना है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकसेवकों को दी चेतावनी, आम लोगों की समस्याओं का तुरंत करें समाधान

एजेन्सी

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि आम लोगों के लिए लाभकारी नए उपाय अपनाने के अलावा उनकी शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना लोकसेवकों का कर्तव्य है। मुर्मू ने यहां राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात करने आए प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया अब एक कुशल और जवाबदेह प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोग सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें तुरंत पोस्ट कर सकते हैं, लोगों तक सेवा प्रदायगी के लिए अद्यतन तरीकों और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई है। मुर्मू ने कहा, ऊर्जावान और जागरूक लोकसेवकों के रूप में, आम लोगों की शिकायतों

और समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आपका कर्तव्य है। आपको ऐसे नवीन उपाय करने चाहिए जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से नागरिकों और देश के लिए फायदेमंद हों। प्रशिक्षु अधिकारी गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) में सुशासन पर केंद्रित 98वां विशेष फाउंडेशन पाठ्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवीनतम प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ 'इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस और अन्य शब्द लोगों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उभरे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, सुशासन नागरिक–केंद्रित शासन का भी प्रतीक है। इन दिनों सरकार की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जनता की प्रतिक्रिया एक कुशल एवं जवाबदेह प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने कहा कि देशभर में तैनात लोकसेवकों की जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की भी है। मुर्मू ने कहा, ''देश के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना आप जैसे लोकसेवकों का कर्तव्य है। भारत के नागरिक देश की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार हैं। आपको विभिन्न कार्यक्रमों के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी क्षेत्र और विभिन्न सुविज्ञ एवं प्रतिबद्ध नागरिकों सहित सभी हितधारकों के सहयोग से ही विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको देश की सेवा के लिए चुना गया है। यह आपका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को देश के समग्र लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए। सबके विकास की इस यात्रा में, आपको हमेशा तैयार रहना होगा और चुनौतियों का सामना करने तथा उन्हें अवसरों में बदलने के लिए तैयार रहें।

उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूर जल्द ही लेंगे खुली हवा में सांस

एजेन्सी

नयी दिल्ली। सरकार ने कहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बहुत सावधानी से लगातार काम चल रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही श्रमिक खुले में सांस ले सकेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य तथा लेफ्टीनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुरक्षा एजेन्सी श्रमिकों तक पहुंचने के काम में जुटी हैं और जो थोड़ी बाधा आयी है उसे दूर कर लिया जायेगा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि बचाव कार्य जल्द शुरू हो जायेगा जिसके बाद श्रमिक खुली हवा में सांस ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एजेन्सी अपना कार्य मुस्तैदी से कर रही हैं जिससे कि आपरेशन को पूरा करने में आने वाली दिक्कतों का तुरंत निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभी श्रमिकों के पास पहुंचने के लिए जो पाइप लगाया जा रहा है वह श्रमिकों से करीब 15 मीटर दूर है। यह पाइप मुड़ गया था और उसको आगे बढाने के लिए रात को उसे काटने का काम किया गया। इसकी मरम्मत कर पाइप को अंदर ले जाने के लिए जल्द ही दोबारा काम शुरु होने की उम्मीद है। लेफ्टीनेंट जनरल ने कहा कि एक रडार लगाया गया है जिससे जमीन के अंदर पांच मीटर तक देखा जा सकता है। इसके जरिए अड़चनों को दूर किया जा रहा है। आपरेशन के लिए यह सकारात्मक प्रगति है और श्रमिकों के बाहर निकलने की सटीक समय सीमा का निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता है। देश के विभिन्न राज्यों की सरकार इसमें अपना यथा संभव सहयोग कर रही है। अभियान से जुड़े तकनीकी अधिकारी विशाल चौहान ने कहा कि अभियान के दौरान इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि फंसे हुए मजदूरों तक बराबर भोजन पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान में श्रेष्ठ तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुरंग की सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों की बराबर मदद ली जा रही है। बचाव काम में लगे विशेषज्ञों का बहुत लंबा अनुभव है।

आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 4 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

एजेन्सी

नयी दिल्ली। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इससे पहले संजय सिंह की कस्टडी 10 नवंबर को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी। जिसे अब फिर से 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और संजय सिंह के पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया। ईडी ने चार अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर छापेमारी और कई घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पांच अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था। फिर कई बार हिरासत की तारीख खत्म होने पर सिंह कोर्ट पहुंचे। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं, संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस नीति को केजरीवाल सरकार ने गड़बड़ी होने आरोपों के बीच 2022 में वापस ले लिया था। ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब नीति में कई डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है। संजय सिंह आबकारी नीति को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका थी और वह रिश्वत के लेन–देन से जुड़े हुए थे।

ज्ञानवापी परिसर विवाद: 'व्यास जी का तहखाना सौंपने से जुड़े मामले में 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

एजेन्सी

वाराणसी। वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी का तहखाना की चाबी जिलाधिकारी को सौंपने से संबंधित मामले की सुनवाई शुक्रवार को कचहरी परिसर में शोक के कारण नहीं कर सकी और अब इसके लिए अगली तारीख 29 नवंबर तय की गई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित 'व्यास जी का तहखाना को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में आज की सुनवाई एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर कचहरी में शोक की वजह से नहीं हो सकी। यादव ने बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ने इस मामले में सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है।

महादेव ऐप मामले में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, केस को क्राइम ब्रांच में किया ट्रांसफर

एजेन्सी

जालंधर। 15 हजार करोड़ रुपए के महादेव ऐप मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इस केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है। मामले में दर्ज एफआईआर में कुल 32 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें सौरव चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी के साथ–साथ जालंधर के रियल एस्टेट कारोबारी चंद्र अग्रवाल भी शामिल हैं। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है और गिरफ्तार असीम दास ने कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने ईडी के निदेशक को पत्र लिखकर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है। दास ने आरोप लगाया है कि उन्हें शुभम सोनी और ईडी अधिकारियों ने फंसाया है। बता दें कि असीम दास को एक कूरियर ब्वॉय के तौर पर गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने दावा किया था कि गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। महादेव ऐप मामले में जालंधर के कथित बिल्डर चंद्र अग्रवाल का नाम सामने आने के बाद पिछले कुछ सालों में उनके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी के बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इनमें से कुछ संपत्तियां विदेशों में बताई जा रही हैं और जालंधर, चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली और गुड़गांव के बाद लुधियाना का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया है, जहां चंद्र अग्रवाल ने मैच फिक्सिंग की काली कमाई से करोड़ों रुपए की संपत्ति और फिरोजपुर रोड, पखोवाल रोड, लाडोवाल बाइपास, गलाडा एस्टेट प्राजैक्ट के लिए मार्क की गई जमीन सामने आई है। इनमें कृषि भूमि के साथ–साथ ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल प्रजैक्ट शामिल हैं। कुछ साइटों की कीमत 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ या 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति गज से अधिक है, जिनकी रजिस्ट्रेशन के लिए करोड़ों रुपए की नकदी का भुगतान कुछ ही दिनों में होने के बाद साइट के निर्माण कार्य भी जोरों पर चल रहा है। इसी बीच यह बात सामने आई है कि साउथ सिटी इलाके में नहर किनारे स्थित एक अन्य कॉम्प्लेक्स में भी चंद्र अग्रवाल का पैसा लगा है। इनमें से पहला कॉम्प्लेक्स बाड़ेवाल की ओर जाने वाली सुई के किनारे पुष्प विहार की जगह पर बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स एफ. 2 रेसवे के साथ बनाया गया है, जहां एक क्लब और रेस्तरां के साथ एक डिस्को भी खोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां चंद्र अग्रवाल का बेनामी पैसा लगा हुआ है। लुधियाना के साउथ सिटी इलाके में नहर के किनारे जिन बिल्डिंग पर चंद्र अग्रवाल का पैसा लगा है, उनके निर्माण में खुलेआम अनियमितता बरती जा रही है। इनमें बाड़ेवाल रोड सुए के किनारे पुष्प विहार की जगह पर बिल्डिंग बनाने के लिए एससीओ का नक्शा पास होने के बाद अब वहां कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन को कवर करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा, जो इमारत एफ. 2 रेसवे के साथ बनाई गई है।

सम्पादकीय

दवा के दावे

भारत में सदियों से ऋषि–मुनियों की सतत साधना से अस्तित्व में आई आयुर्वेदिक दवाओं की स्वीकार्यता रही है। जिसमें प्राकृतिक उपचार और जड़ी–बूटियों के जरिये चिकित्सा की परंपरा पीढ़ी–दर–पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। इस उपचार में आहार–विहार की बड़ी भूमिका भी रही है। लेकिन वक्त के साथ आयुर्वेदिक दवाओं का बड़ा बाजार तैयार हुआ है। इस ऋषिकर्म के कारोबार बनने के अपने खतरे हैं। पहले गरीब लोग, जो महंगे एलोपैथिक उपचार करने में सक्षम नहीं होते थे, गांव–देहात के वैद्यों से अपनी माली हालत के चलते उपचार कराते थे। लेकिन कालांतर बड़ी पूंजी के कारोबारी इस धंधे में कूदे और आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री के लिये विज्ञापनों के जरिये बड़े–बड़े दावे करने लगे। हाल ही में एलोपैथिक चिकित्सकों के एक राष्ट्रीय संगठन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके देश के एक बहुचर्चित योगी के आयुर्वेदिक उपचार के दावों की सार्थकता पर सवाल उठाये थे। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद कंपनी के कर्ताधर्ताओं को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने भ्रामक दावों और उससे जुड़े विज्ञापनों के खतरों की याद दिलायी। दरअसल, हर्बल उत्पादों के जरिये होने वाले उपचार के परिणामों की तुलना आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की खामियों के साथ करने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को आपत्ति थी। यही वजह है कि कोर्ट का कहना पड़ा है कि हर्बल उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनी के कर्ताधर्ताओं को चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के बारे में अनावश्यक बयान देने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चेताया कि यदि किसी बीमारी विशेष को ठीक करने वाली दवाओं के बारे में गलत ढंग से दावा किया गया तो एक करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने एक याचिका में आरोप लगाया है कि विज्ञापनों में एलोपैथी को अपमानित किया गया। इसके साथ ही असत्यापित दावों के जरिये डॉक्टरों की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। जिससे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से जुड़े लोग खुद को आहत महसूस कर रहे हैं। दरअसल, राजग सरकार के दौरान राजाश्रय में देश में योग व आयुर्वेद का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ है। साथ ही भारतीय परंपरागत पूरक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। भारत ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर पूरक चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय की कोशिश की गई है। इसमें दो राय नहीं कि लगातार महंगी होती एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के भी अपने किंतु–परंतु हैं। लेकिन इसके बावजूद दवाओं की विश्वसनीयता और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कानूनों का अतिक्रमण करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अब चाहे वह एलोपैथिक उपचार हो या आयुर्वेद से जुड़ा उपचार। निश्चित रूप से अब चाहे आधुनिक चिकित्सा से जुड़े उत्पाद हों या आयुर्वेद से जुड़े, सबको इन्हें बढ़ावा देने का अधिकार है। लेकिन प्रचार के जरिये दूसरे की रेखा मिटाने या छोटा करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। ये कारोबार के नैतिक नियमों का भी उल्लंघन है। दरअसल, आईएमए ने अपनी याचिका में एलोपैथी और इसके चिकित्सकों के बारे में दिये गये बयानों को भ्रामक व मिथ्या दावों पर आधारित बताया था। साथ ही नियामक अधिकारियों की निष्क्रियता और उदासीनता की ओर भी इशारा किया गया। उल्लेखनीय है कि बीते साल भी कोविड–19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ प्रचार के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था। निस्संदेह, शीर्ष अदालत ने अपनी गरिमा के अनुकूल कहा कि वह इस मामले को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती। उसका मकसद सिर्फ भ्रामक विज्ञापनों का एक व्यावहारिक समाधान ढूंढना ही है। इसके लिये केंद्र सरकार से व्यावहारिक उपाय पेश करने को कहा गया है। जिसमें चिकित्सा प्रणाली से जुड़े किसी भी विज्ञापन की सख्त और निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी बल दिया कि उपचार से जुड़े किसी भी भ्रामक विज्ञापन को तुरंत हटाया जाना चाहिए। साथ ही सख्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए। निस्संदेह, स्वास्थ्य हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है।

हिंदी से बढ़ता वैश्विक व्यवसाय

संजीव ठाकुर

वर्तमान में हिंदी को वैश्विक स्तर पर उपभोक्तावाद से जोड़ा गया है। और बीच–बीच में हिंदी के मध्य उर्दू और अंग्रेजी ने अपनी जगह बनाई है। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में ही हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी के कई शब्द मिलाकर हिग्लिश भाषा बोली जाती है। न्यूज चौनल में न्यूज एंकर विशुद्ध हिंदी की जगह हिग्लिश ही बोलकर अपनी इतिश्री कर लेते हैं। और तो और अब हिंदी के बड़े साहित्यकार भी हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्द मिलाकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और पढ़ रहे हैं। विडंबना यह है कि भारत में 140 उपभोक्ता की उपस्थिति में विशुद्ध हिंदी का प्रयोग करना थोड़ा कठिन हो जाता है।जैसे हम टी,वी, को दूरदर्शन नहीं कहते, इंटरनेट को इंटरनेट ही लिखा जाता है, अंतरजाल नहीं लिखा जाता ।यह जितनी अंग्रेजी की शब्दावली हिंदी में जुड़ी हुई है,यह संचार माध्यम टी,वी व्हाट्सएप,फेसबुक,ट्विटर, इंटरनेट सीधे–सीधे उपभोक्ताओं के बाजार वाद के कारण जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में लगभग 140 करोड़ उपभोक्ता निवास करते हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी तथा उर्दू की मिलावट के साथ किया जाता है। वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो हिंदुस्तानी मूल के लोग श्रीलंका,मॉरीशस,फिजी, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा,ऑस्ट्रेलिया,न्यू जीलैंड, साउथ अफ्रीका में फैले हुए हैं। ऐसे में हिंदी का वैश्विक विस्तार अपने आप हिंदी भारतीय अप्रवासी, प्रवासी भारतीय लोगों के माध्यम से होने लगता है।फिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रॉस, इटली, जापान,चाइना इनके उत्पादक को भारत के उपभोक्ताओं के बीच बेचने के लिए उन्हें हिंदी की आवश्यकता होती है, भारत एक शक्तिशाली उपभोक्ता बाजार है। एक साथ एक ही जगह इतने ग्राहक मिलना किसी अन्य देश में असंभव है। इन परिस्थितियों में विश्व का हर देश अपने बनाए गए उत्पादन का बाजार खोजने भारत की ओर खिंचा चलाआता है। और हिंदी को माध्यम बनाकर वह अपना माल बेचना शुरू करता है। और इसके लिए टी,वी, इंटरनेट, कंप्यूटर,व्हाट्सएप तथा फेसबुक में हिंदी में विज्ञापन देकर उसका प्रचार प्रसार करता है। विज्ञापनों में हिंदी का व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार वैश्विक स्तर पर होने लगा है।

डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने भाषा शोध अध्ययन 2012 में यह दावा किया है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी में अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं का उपयोग करने वालों को पीछे छोड़ दिया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था। इसी तारतम्य में भारत में प्रत्येक पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में व्यापक स्तर पर देश की राजधानी दिल्ली चलेगी ग्राम पंचायत तक मनाया जाता है। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा है हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द या भाषा का तिरस्कार नहीं किया। वैसे भी अंग्रेजों के आगमन के पूर्व हिंदी देवनागरी लिपि में उर्दू तथा फारसी शब्दों का समावेश होता रहा है। अंग्रेजों के आने के बाद इसने अंग्रेजी शब्दों को भी आत्मसात किया। हिंदी एक विशाल हृदय की विशाल भाषा है। इसमें अन्य भाषा के अपभ्रंश आने से हिंदी कभी मूल रूप से दिग्भ्रमित या विकृत नहीं हो पाई है। यही वजह है कि हिंदी वैश्विक स्तर पर धीरे–धीरे विस्तारित, प्रचारित एवं प्रसारित होती जा रही है। वर्तमान में विश्व में लगभग 45 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसकी सरलता विश्व के लोगों को प्रभावित करती जा रही है, भारत के विद्वानों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, कवियों, फिल्मी गीतकारों के प्रयासों से हिंदी ने वैश्विक रूप लिया है। हिंदी को वैश्विक रूप से उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए फिल्म निर्माताओं गीतकार एवं संगीत, गानों का भी बड़ा योगदान रहा है। हिंदुस्तान में बनी फिल्म को विदेशों में रह रहे भारतीय तथा अन्य भाषाई लोग उसके गीतों तथा उसके संवाद के कारण उस फिल्म को देखने जाते हैं, जिससे सीधे–सीधे भारतीय फिल्मकारों को विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। इस तरह उपभोक्तावाद, बाजारवाद के नजरिए से देखें तो हिंदुस्तानी उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा बाजार वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है। जिससे हिंदी भाषा न सिर्फ बाजारवाद की भाषा बनी है, बल्कि साहित्यिक रूप से भी गीत, गजल और गानों के रूप में समृद्ध हुई है। वर्तमान में हिंदी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय होती जा रही है। भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना कर एवं वैश्विक स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन अलग–अलग देशों में आयोजित किया जाता रहा है। इस संदर्भ में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार तथा विस्तार को कोई भाषा रोक नहीं सकती है। हिंदी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषा वासी लोग आपस में अपने विचारों का आदान–प्रदान सकते हैं। एनी बेसेंट ने हिंदी भाषा को लेकर काफी सत्य कहा है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में जो भाषा सबसे प्रभावशाली बन कर सामने आती है वह हिंदी है। वह व्यक्ति जो हिंदी जानता है पूरे भारत में किसी भी प्रांत की यात्रा कर सकता है और हिंदी बोलने वालों से हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार पूर्णता हिंदी में करना शुरू कर दिया। इसी तारतम्य में यदि यह कहा जाए कि हिंदी वैश्विक बाजार वाद या उपभोक्तावाद की सबसे बड़ी एवं सशक्त भाषा बन गई है, तो यह अतिरेक नहीं होगा। अंग्रेजी जरूर अंतर राष्ट्रीय भाषा है,पर हिंदी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली द्वितीय भाषा तो जरूर है ही, एवं उपभोक्ताओं के लिए यह प्रथम स्थान रखती है।भारत में हिंदी भाषा सभी प्रांतों सभी राज्यों को एकता के सूत्र में पिरोने वाली एक मातृभाषा स्थापित रूप से है। इसीलिए इसे राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का वास्तविक सम्मान दिए जाने की आवश्यकता है।

रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा

योग गुरु के रूप में प्रसिद्धि पाने के बाद आयुर्वेदिक दवाओं के व्यवसाय में उतरे बाबा रामदेव जैसे–जैसे ख्याति पाते गये, वे नये–नये विवादों में भी घिरते गये हैं। प्रारम्भ में तो उनकी सराहना हुई कि उन्होंने भारतीयों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। उनके योग शिविरों में लोगों ने भारी–भरकम शुल्क देकर योग सीखा। इसके बल पर उन्होंने अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया।अंग्रेजी दवाओं के खिलाफ उन्होंने बड़ा अभियान चलाया। इसे उन्होंने भारत की परम्परागत उपचार विधि पर हमला बताया। बाद में वे हरिद्वार के अलावा विभिन्न राज्यों में स्वयं के आयुर्वेदिक दवाओं के कारखाने खड़े करते गये तथा एक तरह से उनके पास हर बीमारी का इलाज मानों उपलब्ध था। वैसे तो उनके इलाज एवं दवाओं को प्रारम्भ से ही आधुनिक प्रणाली के लोग शंका की नजर से देखते रहे हैं, परन्तु अपने प्रचार तंत्र और सत्ता से नजदीकियों के कारण उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कभी नहीं की जा सकी। अलबत्ता अब सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि को कड़ी फटकार मिली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से दायर एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके उत्पादों को लेकर किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन जारी किये गये तो हर विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। शीर्ष कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह देते हुए यह भी कहा कि ऐसा प्रेस बयान भी न दिया जाये जिससे कोई भ्रम फैले। वैसे सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी के बाद रामदेव ने यह आरोप लगाया कि पतंजलि के खिलाफ ड्रग माफिया द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि वे कोई गलत प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर रामदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पतंजलि कोई गलत प्रचार करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। रामदेव ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष

स्वास्थ्य लाभ लिये हुए मरीजों की परेड करने की भी चुनौती देते हुए कहा कि गलती करने पर वे एक हजार करोड़ रुपये का जुर्माना भरने व फांसी चढ़ने के लिये भी तैयार हैं। रामदेव पहले तो योग करने–कराने में व्यस्त रहे लेकिन बाद में उन पर देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का भूत सवार हो गया। वे एक दशक पहले हुए अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़ गये थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि जब वे दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे धरने में भाग लेने के लिये पहुंचे थे। यह अलग बात है कि आंदोलन को खत्म करने के लिये जब लाठी चार्ज हुआ तो मंच से कूदकर भागने वालों में वे सबसे आगे थे। उनके अनुयायियों ने उन्हें महिला के कपड़े पहनाकर सुरक्षित निकाला था। मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने में जिन लोगों का प्रमुख हाथ था उनमें रामदेव भी थे। उनका दावा था कि अगर विदेशों में भारतीयों का रखा कथित भ्रष्टाचार का पैसा वापस आ जाये तो पेट्रोल पानी के भाव से मिलेगा और हर गांव समृद्ध होगा। उनकी भारतीय जनता पार्टी तो डॉ. मनमोहन सिंह की तत्कालीन कांग्रेस प्रवर्तित केन्द्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री उन्हें लेने व मनाने पहुंचे से नजदीकियां बढ़ती चली गयीं। बताया जाता है कि अनेक राज्यों में उन्हें दवा निर्माण के लिये फैक्ट्रियां लगाने के लिये बहुत सस्ते में जमीनें मिल गयीं। हालांकि उन पर आरोप है कि उनकी दवाएं अमानक होती हैं तथा बहुत से ब्रांड उन्होंने आऊटसोर्स कर दिये हैं। यानी वे खुद नहीं बनाते। यह जानकर कि उनके प्रति लोगों का विश्वास व श्रद्धा इतनी है कि वे किसी भी कीमत पर उनकी दवाएं खरीद लेंगे, पतंजलि के उत्पाद काफी महंगे होते हैं व देश भर में उनकी दवाओं की मांग है। अब रामदेव केवल दवा नहीं बनाते बल्कि खाद्य सामग्रियां, सौंदर्य प्रसाधन का उत्पादन भी करते हैं। विदेशी संस्कृति की आलोचना करने वाले, भगवा वस्त्रधारी रामदेव को जीन्स के परिधान बनाने से भी परहेज नहीं रह गया। उनके उत्पादों पर कई बार आपत्तियां उठाई गईं लेकिन सत्ताधीशों के समर्थन से उन पर आंच तक न आई। भ्रष्टाचार व महंगाई पर वे अब कुछ नहीं कहते। कोरोना काल में भी रामदेव ने भ्रम फैलाने का कार्य किया। जब करोड़ों लोग आधुनिक तकनीकों से किए गए शोधों के आधार पर एलोपैथी प्रणाली के टीके व दवाओं से अपनी जान बचा रहे थे, रामदेव ने इसकी निरर्थकता का प्रचार करते हुए आनन–फानन में तैयार अपने उत्पादों को रामबाण बतलाते हुए उसे बड़े पैमाने पर बेचा। आईएमए ने इस पर आपत्ति उठाई कि पर्याप्त शोध एवं आवश्यक अवधि तक प्रभाव देखे बिना पतंजलि अपनी कथित कोरोनारोधी दवाएं बेच रहा है। इस पर अपने समर्थकों, अनुयायियों एवं मुख्य धारा के मीडिया के जरिये एलोपैथी प्रणाली के खिलाफ उनके द्वारा अभियान ही छेड़ दिया गया। यहां तक कि संस्था को ईसाई बतलाया गया। उस दौरान उठे एलोपैथी बनाम आयुर्वेद विवाद का फायदा भी उन्होंने जमकर उठाया। परिणामस्वरूप कई लोगों ने एलोपैथी की बजाय पतंजलि के उत्पाद लेने प्रारम्भ किये। योग से शुरू कर रामदेव की बनाई मल्टी–प्रोडक्ट्स वाली कम्पनी से किसी की दुश्मनी नहीं है। हर कोई अपना व्यवसाय कर सकता है लेकिन उसके लिये सभी आवश्यक नियमों का पालन जरूरी है। विशेषकर लोगों को भ्रमित कर अपना व्यवसाय करना सामाजिक हितों के खिलाफ है क्योंकि अमानक दवाएं हों या खाद्य सामग्रियां, वे जानलेवा होती हैं।

भारत-ब्रिटेन में एफटीए पर बात बढ़ी आगे

भारत और ब्रिटेन के बीच आगामी कुछ दिनों में मुक्त व्यापार वार्ता समझौते पर सहमति बनने की उम्मीद की जा रही है। दोनों ही देशों में अगले साल आम चुनाव होने हैं और भारत–ब्रिटेन के प्राधिकार चाहेंगे कि इस समझौते को इन आम चुनावों से पहले अमली जामा पहना दिया जाए। अगर ऐसा करने में सफलता मिलती है तो ब्रिटेन में सत्ताधारी पार्टी को अपने मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलेगी। भारत में इसका असर देखने को मिल सकता है। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस करार को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के क्रम में वे चाहते हैं कि भारत के साथ एफटीए पर अंतिम सहमति बनने से पहले हर पहलू पर अच्छे से विचार हो ताकि ब्रिटिश हितों को नुक्सान नहीं पहुंचे। अभी दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार भारत के पक्ष में झुका है। भारत का निर्यात ब्रिटेन के लिए लगातार बढ़ रहा है जबकि ब्रिटेन से भारत का आयात बढ़ा तो है लेकिन अभी उसकी गति बेहद कम है। अगर मुक्त व्यापार समझौता इस साल के आखिर तक हो जाता है तो इससे दोनों देशों में आर्थिक विकास और रोजगार के मौके को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आयात–निर्यात के बीच का ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत आयात–निर्यात के इस अंतर को बढ़ा सकता है। ब्रिटेन में भारतीय सामान की अच्छी खासी मांग रहती है जिसका दोहन भारतीय व्यापारी कर सकते हैं। अगर एफटीए पर सहमति बन जाती है तो ब्रिटेन को अपनी प्रीमियम कारों, व्हिस्की और कानूनी सेवाओं के लिए भारत जैसे बड़े बाजार में पहुंच बनाने में आसानी होगी। ब्रिटेन 2020 में यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद से ही अपने वैश्विक व्यापार में विविधता लाने के मकसद से नए–नए साझेदारों की तलाश में है और इस लिहाज से भारत का बड़ा बाजार उसके लिए काफी कूटनीतिक मायने रखता है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार 2021–22 में 17.5 अरब डॉलर था। 2022–23 में ये आंकड़ा बढ़कर 20.42 अरब डॉलर हो गया। कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री के मुताबिक अगर एफटीए हो गया तो ये 2035 तक भारत के साथ व्यापार को 28 बिलियन पाउंड प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ब्रिटेन, भारत से मुख्य तौर से रेडीमेड परिधान और कपड़े, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, पैट्रोलियम और पैट्रो रसायन उत्पाद के साथ ही परिवहन उपकरण, मसाले, मशीनरी, फार्मास्युटिकल्स और समुद्री उत्पाद बड़े पैमाने पर खरीदता है। जबकि भारत ब्रिटेन से बहुमूल्य रत्न, अयस्क, धातु कबाड़, इंजीनियरिंग सामान के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, रसायन और मशीनरी खरीदता है। रूस को छोड़ दें तो यूरोपीय देशों में फिलहाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार नीदरलैंड्स है और उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है। इस मामले में यूनाइटेड किंगडम यूरोप में भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है। भारत–ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ब्रिटेन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एफटीए में इमीग्रेशन यानी आप्रवासन पर प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं होंगी और न ही ब्रिटेन के घरेलू श्रम बाजार तक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। इस मसले को यूनाइटेड किंगडम के व्यापार राज्य सचिव केमी बडेनोच ने पहले ही साफ कर दिया है। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन को भारत का स्वाभाविक साझेदार बनने के लिये अपने देश के कड़े कानूनों में बदलाव करना होगा। भारतीय इकोनॉमी लगातार ग्रोथ कर रही है और इसके जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद की जा रही है। ब्रिटेन की सुनक सरकार का मानना है कि भारतीय बाजार के दोहन से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर आने पर जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई की जा सकेगी। भारतीय बिजनेस लॉबी भी इस बातचीत का इंतजार कर रही है क्योंकि इससे उनके लिये ब्रिटेन के दरवाजे अच्छी तरह खुल जाएंगे और ब्रिटेन के साथ–साथ पूरे यूरोप में चीन का मुकाबला करने में आसानी होगी। भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों चाहते हैं कि इस साल ही मुक्त व्यापार समझौता हो जाए। ऐसे में 2023 का साल भारत के लिए यूरोप के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।

स्थानीय आरक्षण की बहस क्या अब खत्म होगी?

अजीत द्विवेदी

हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी सीटें आरक्षित करने के राज्य सरकार के कानून को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस ममले में बहुत स्पष्ट और दो टूक फैसला सुनाया है। पहले 2022 में भी अदालत ने इस कानून पर रोक लगा दी थी लेकिन तब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह विस्तार से सुनवाई करके गुण–दोष के आधार पर इस कानून के बारे में फैसला सुनाए। सो, हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने विस्तार से यह मामला सुना और 83 पन्नों का फैसला लिखा। अदालत ने संविधान के कई अनुच्छेदों के हवाले से इस कानून को भेदभाव वाला बताते हुए खारिज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार ने भी स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का कानून बनाया था। उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि यह कानून असंवैधानिक हो सकता है। लेकिन गुण–दोष के आधार पर उसके बारे में अंतिम फैसला नहीं आया है। कई और राज्यों में सरकारें इस तरह के कानून की तैयारी कर रही हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा वादा किया हुआ है। तभी पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि क्या अब स्थानीयता के आधार पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण देने की बहस स्थायी तौर पर समाप्त हो जाएगी?

असल में हरियाणा की भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो हरियाणा के स्थानीय युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों में आरक्षण का कानून बनाएगी। 2019 के अंत में सरकार बनने के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री ने इस वादे को पूरा करने के लिए कानून बनाने की पहल की और एक साल पूरा होने पर नवंबर 2020 में कानून बना दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि निजी क्षेत्र में 30 हजार रुपए मासिक वेतन से कम वाली नौकरियों में 75 फीसदी नौकरियां हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी। मार्च 2021 में राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दी और 2022 की जनवरी से यह कानून लागू हो गया।

हरियाणा सरकार के इस कानून के मुताबिक राज्य में काम करने वाली हर तरह की निजी संस्था को इसके दायरे में रखा गया। सिर्फ उद्योग नहीं हर तरह की कंपनियां, संस्थाएं, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, जिनके कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है उनको इसके दायरे में रखा गया। इतना ही नहीं इस कानून की धारा छह में यह प्रावधान किया गया कि कंपनियों के लिए जरूरी होगा कि वे हर तीन महीने पर अपनी रिपोर्ट सरकार को जमा करें, जिसमें बताएं कि कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई। कानून की धारा आठ के तहत संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया गया कि वे कंपनियों से उनके रिकॉर्ड मांग कर चेक कर सकते हैं कि कंपनियां कानून का पालन करके स्थानीय लोगों को नौकरी दे रही हैं या नहीं। कानून की धारा 20 के तहत यह प्रावधान किया गया कि श्अच्छी मंशाश से काम कर रहे किसी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है।

कानून के प्रावधानों को देख कर पहली नजर में पता चल जाता है कि राजनीतिक या चुनावी वादा पूरा करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया है, जिसे संविधान के दायरे में लागू करना मुश्किल होगा। पहली नजर में यह कानून संविधान के कई प्रावधानों के विरूद्ध दिखाई देता है। यह अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। नागरिकों के समानता के सिद्धांत के खिलाफ दिखता है। भारत का संविधान देश के नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी करने या रोजगार करने का अधिकार देता है। नागरिकों से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता है। यह निजी उद्यमियों के अपने कारोबार के लिए योग्य लोगों को नियुक्त करने के अवसर को कम करता है।

इसी आधार पर हरियाणा सरकार के इस कानून को अदालत को चुनौती दी गई थी। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और राज्य के अन्य उद्योग समूहों ने इस कानून को चुनौती दी। कानून के विरोध में याचिका देने वालों का कहना था कि यह कानून कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह दलील भी दी थी कि निजी सेक्टर की नौकरियां पूरी तरह से योग्यता, कौशल और काम को समझने की क्षमता के आधार पर दी जाती हैं। उसमें धरती पुत्र के नाम पर आरक्षण करने से कंपनियों या उद्योगों का काम प्रभावित होगा। उद्योग समूहों का यह भी कहना था कि निजी सेक्टर में क्षेत्र के आधार पर आरक्षण देना संविधान की संघीय भावना के विपरीत होगा। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना था कि संविधान में ही इस बात का प्रावधान है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई खास समूह पिछड़ा है और नौकरियों में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो नौकरियों में समानता के सिद्धांत के बावजूद वह आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कानून के कई प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून इंस्पेक्टर राज की बहाली का रास्ता बनाता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस कानून के जरिए राज्य सरकार निजी सेक्टर की कंपनियों में नियुक्ति पर अपना संपूर्ण नियंत्रण चाहती है। इस आधार पर अदालत ने इस कानून को रद्द कर दिया। हालांकि यह मामला यही पर समाप्त नहीं होगा। राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा सरकार की चुनौती मेरिट पर नहीं होगी, बल्कि अपना चेहरा बचाने के लिए होगी। चूंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के एक दल ने मतदाताओं से वादा किया था कि वह उनके लिए तीन–चौथाई नौकरियां आरक्षित कराएगा इसलिए उसकी मजबूरी है कि वह सर्वोच्च अदालत तक यह मामला ले जाए ताकि लोगों के बीच यह संदेश जाएगा कि पार्टी ने वादा किया था तो उसे पूरा करने का प्रयास भी किया। हालांकि वादा करने वाली पार्टी को भी पता है कि उसका वादा तर्कसंगत नहीं है। संविधान के अनुकूल नहीं है और न प्रतिस्पर्धा के मौजूदा दौर में निजी उद्यमों के लिए अच्छा है।

यह समझने की जरूरत है कि कंपनियां या उद्योग समूह राजनीतिक दलों के वादे पूरे करने का माध्यम नहीं बन सकती हैं। उनको अगर प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है तो योग्य, कुशल व सस्ता मजदूर या पेशेवर चाहिए। यह सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है। किसी भी राज्य में कंपनियों या उद्योग समूहों को अगर देश के पिछड़े राज्यों, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि से सस्ते और कुशल मजदूर मिल रहे हैं तो वह क्यों आरक्षण की नीति के तहत स्थानीय युवाओं को नियुक्ति करेंगे? तीन चौथाई स्थानीय युवकों को नियुक्त करने का एक नुकसान यह भी है कि वहां वे संगठित होकर प्रबंधन के ऊपर दबाव बना सकते हैं।

हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जलालपुर थान अंतर्गत शुक्रवार शाम को क्षेत्र के लहंगपुर ग्राम स्थित वाराणसी जौनपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान जलालपुर पुलिस टीम ने हत्या करने वाले अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त वाहन स्वीफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार किया है।इस मामले में इंस्पेक्टर राजेश यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डा अजय पाल शर्मा के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी केराकत गौरव शर्मा के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर लाइन बाजार मय हमराह द्वारा थाना जलालपुर जौनपुर से सम्बन्धित

वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तगण हत्या में प्रयुक्त वाहन स्वीफ्ट डिजायर से वाराणसी से लखनऊ की तरफ जा रहे है। उक्त सूचना पर बार्डर पर चार पहिया वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था कि वाराणसी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही उक्त स्वीफ्ट डिजायर कार को रोका गया तो उक्त वाहन मे बैठे व्यक्ति भागने का कोशिश किये जिसे पुलिस टीम ने घेर कर पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति में विपिन विश्वकर्मा पुत्र रामलाल विश्वकर्मा ,राकेश पासवान पुत्र केशर पासवान,नन्द किशोर सिंह उर्फ भोला पुत्र स्व0 जमुना सिंह निवासीगण ग्राम परशुराम पुर थाना अलीनगर,चन्दौली बताया गया। बीते रविवार की रात्रि में लल्लन पासवान पुत्र रामजी पासवान निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना अलीनगर जिला चन्दौली को स्वीफ्ट डिजायर कार से लाकर बीबनमऊ थाना लालपुर जौनपुर के सई नदी पुल से हत्या के नियत से उठाकर नदी में फेक दिये जिससे लल्लन पासवान की मृत्य हो गयी मृतक का शव बुधवार को सई नदी ग्राम ताला मझवारा थाना जलालपुर जौनपुर में मिला था। सभी हत्या आरोपी को अभियुक्तगणों को घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधिकारी ने मतदान बूथों का किया निरीक्षण बीएलओ द्वारा कमी पाए जाने पर पुन: सर्वे करने का दिया निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के द्वारा कंपोजिट विद्यालय पंचहटिया के बूथ संख्या 205, 206 एवं इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, चौकीपुर के बूथ संख्या 213, 214, अभिनव इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल जपटापुर के बूथ 95, 96, 97, आदर्श कन्या इंटर कालेज के बूथ संख्या 113, 114, 115, 116, 117 एवं प्राथमिक विद्यालय खेतासराय के बूथ संख्या 111, 112 का निरीक्षण किया गया।

कंपोजिट विद्यालय के निरीक्षण के दौरान पाया कि बीएलओ के द्वारा सर्वे रजिस्टर ठीक से नही भरा गया है। जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा फिर से सर्वे हेतु निर्देश दिया गया। अभिनव इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल जपटापुर के के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि सर्वे ठीक से नहीं किया गया है। पुरुष मतदाता की अपेक्षा महिला मतदाता बहुत ही कम जोड़े गए हैं जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सुपरवाइजर को निलंबित करने के निर्देश दिए गये। प्राथमिक विद्यालय खेतासराय के निरीक्षण में बूथ संख्या 111 में सर्वे का कार्य सही नही पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। बूथों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा बीएलओ से जानकारी ली गई कि बीएलओ के द्वारा कितने फॉर्म 7 व 8 के लिए गए हैं। जिलाधिकारी के द्वारा शिफ्टेड मतदाताओं, विवाहित महिलाओं का सत्यापन व अन्य सम्बंधित जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मतदाता सूची का सर्वे सही तरीके से किया जाए। जिन महिलाओं का विवाह हो गया है उनका चिन्हाकन कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है वे तथा अर्ह लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराये, नाम जोड़ने व दावा आपत्ति 9 दिसम्बर 2023 तक प्राप्त किया जायेगा तथा 26 नवम्बर व 02, 03 दिसम्बर को भी सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बैठेगे। इस अवसर का लाभ उठाये। विशेषकर 18–19 वर्ष के युवा व महिलाओं को मतदाता बनाने के लिए जागरुक करें।

इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा उक्त विद्यालयों में शिक्षकों तथा छात्रों की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया और प्रधानाध्यापकध्अध्यापकों को निर्देशित किया कि बच्चों को अधिक से अधिक लेखन का अभ्यास कराये तथा बच्चों को साफ–सफाई के बारे में जागरुक करने हेतु भी निर्देशित किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर ऋषभ देशराज पुंडरीक, उप जिलाधिकारी शाहगंज शैलेंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही।

प्रधानमंत्री पर पनौती शब्द का इस्तेमाल सरासर गलत: जावेद आब्दी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए इस्तेमाल की गयी पनौती शब्द की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि किसी बड़े बजुर्ग के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नही करना चाहिए जिससे उनका व उनके समर्थको का दिल टूटे। राजनीतिक विरोध करना है तो अच्छे शब्दो का प्रयोग करना चाहिए। जावेद आब्दी शुक्रवार को मल्हनी विधानसभा के दक्षिण पट्टी बबरखा में एक चालीसवें के मजलिस में शिरकत करने के बाद पत्रकारो से बातचीत कर रहे थे।

उन्होने हलाल ब्राण्ड को यूपी प्रतिबंधित किये जाने का सवाल पर कहा कि हमारा सविधान में हर व्यक्ति को खाने पीने पहनने की आजादी है ऐसे में हलाल ब्राण्ड को प्रतिबंधित करने से जनता को कोई फायदा नही होगा बल्कि जो गरीब तबके के लोग ठेला पर नानवेज बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते है उनका नुकसान जरूर होगा।

उन्होने कहा कि हमारी पार्टी का बस एक ही उद्देश्य है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है इसके लिए केन्द्रीय नेतृत्व गठबंधन करके रणनीति तैयार कर रही है।

थाना समाधान दिवस में अफसरों ने सुनी फरियादियों की शिकायत

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' माह के अंतिम शनिवार को पाली थाने पर अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) दुर्गेश सिंह व शाहाबाद उपजिलाधिकारी पूनम भास्कर की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें काफी संख्या में लोगों ने

पहुंचकर अपनी –अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस से संबंधित जन समस्याओं के निस्तारण करने को संबंधित अधिकारियों को पहली प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने बारी–बारी से फरियादियों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कुछ समस्याओं को लेकर अपने– अपने अधिनस्थों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी प्रार्थना पत्रों का हर हाल में निस्तारण कर दिया जाये। इसमें किसी कर्मचारी ने लापरवाही की तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने पुलिस स्टॉफ को निर्देश देते हुए ।

मसौधा मे न्याय पंचायत स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

अयोध्या। शनिवार को न्याय पंचायत माधवपुर विकासखंड–मसौधा की न्याय पंचायत स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कंपोजिट विद्यालय खानपुर मसौधा में आयोजित किया गया।प्रतियोगिता में न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया।प्रतियोगिता शिक्षक संकुल आकांक्षा विश्वकर्मा,सुषमा गुप्ता,मनीषा पांडेय,आरती यादव व दीपमाला श्रीवास्तव के नेतृत्व में सम्पन्न हुई।इस मौके पर माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।इसके बाद न्यायपंचायत के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों की प्राथमिक एवं जूनियर स्तर पर 50मीटर, ,100मीटर, 200 मीटर दौड़,कबड्डी,खो खो,गोला फेक,एवम सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।निर्णायक मंडल में ध यानचंद यादव,बृजेश कुमार ,आरती यादव एवम पुष्पा मौर्या का विशेष सहयोग रहा।सभी प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने सामर्थ्य ने विद्यालय का नाम रोशन किया।अंत मे प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय एवम तृतीय स्थान पर आए बच्चो को ब्लॉक मोबीलाइजेसन कोर्डिनेटर (बी एम सी,) धीरेंद्र नाथ पांडेय,अमिताभ सिंह ,पूर्व एन पी आर सी, ध्यानचंद यादव , बृजेश कुमार,आकांक्षा विश्वकर्मा,आरती यादव, पुष्पा मौर्या , नीतू सिंह द्वारा पुरस्कृत कर बच्चो को ब्लॉक स्तरीय रैली में भी बेहतरीन तैयारी के साथ प्रदर्शन किए जाने की शुभकामनाएं दी गई।

टीडी कश्लेज मेब बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से लागू : प्राचार्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से लागू की गई ,जिसमें अभी लगभग 42 स्थायी प्राध्यापक एवम् 23 स्ववित्त पोषित प्राध्यापको ने बायोमेट्रिक मशीन पर फेस रीडिंग एवं अंगूठे के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. आलोक कुमार सिंह ने बताया कि शासन के कार्य निर्देश के बाद बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है, जिसमें निदेशक उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी तथा प्रबंधक के आदेश के क्रम में यह उपस्थिति अनिवार्य की गई है, इसके संदर्भ में सभी सम्मानित प्राध्यापकों को अवगत कराया गया है, जिन प्राध्यापकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है उनके दिसंबर वेतन आहरण में निश्चित रूप से रुकावटें आएगी, प्राचार्य प्रो.आलोक कुमार सिंह ने कहा कि, यह शासन की मंशा है, इस पर सभी सम्मानित प्राध्यापको से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। जिन प्राध्यापकों द्वारा दिनांक 30 नवंबर तकबायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, उनका वेतन बिल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होगा, क्यों की एक दिसंबर 2023 से ब्योमेट्रिक अनिवार्य रूप से लागू की गई है, एक दिसंबर से रजिस्टर उपस्थित समाप्त हो जाएंगी।

विश्व की सुंदरतम नगरी बनने की ओर अग्रसर अयोध्या

वैश्विक पटल पर छा जाएगी अयोध्या : मृत्युंजय दीक्षित

हरदोई (अंबरीश कुमार सक्सेना)। 500 वर्षों के अथक संघर्ष के पश्चात नौ नवंबर 2020 को माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा अयोध्या पर राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय देने के बाद, श्रीराम जन्मभूमि पर श्री रामलला के भव्य दृदिव्य मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से सम्पूर्णता की दिशा में अग्रसर है । मंदिर के भूतल का लगभग 95 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगामी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना भी सुनिश्चित हो गया है। कुछ वर्ष पूर्व तक जो अयोध्या नगरी हिन्दुओं के संघर्ष की धरती थी जो आगामी 22 जनवरी 2024 को सर्व संतोषकारिणी नगरी बनने जा रही है। लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्रीराम लला अपने जन्मभूमि आवास में पधार रहे हैं और प्रत्येक सनातनी यह सोचकर हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है कि अयोध्या में श्रीरामलला के विराजमान हो जाने के बाद उनके सभी दुखों व चिंता का निवारण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में आनंद की बयार बह रही है और हो भी क्यों न हम सबके श्रीराम अपने घर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार अयोध्या को अखिल विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। एक समय था जब रामभक्त अयोध्या दर्शन करने जाते अवश्य थे किंतु हनुमानगढ़ी और कनक भवन के दर्शनों तक सीमित रह जाते थे और बहुत कम श्रद्धालु श्री रामजन्मभूमि के दर्शन करने के लिए जाते थे क्योंकि तम्बू में बैठे भगवान तक पहुंचना सरल नहीं था किन्तु उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद परिवर्तन आया और 22 जनवरी 2024 के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदलने जा रही है क्योंकि अब रामभक्तो व श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा पूर्ण और धैर्य समाप्त हो रहा है।

भव्य श्रीरामलला मंदिर के उद्घाटन के पश्चात श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है, अयोध्या में उनके भव्य स्वागत, रहने –ठहरने व दिव्य दर्शन सुलभ करने के लिए व्यापक प्रबंध किये जा रहे हैं। अयोध्या व उसके आसपास के समस्त क्षेत्र को इस प्रकार से निर्मित किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को त्रेतायुग के समय का आभास हो और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से जुटे हैं । विगत कई वर्षों से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयेजन किया जा रहा है जिसमें प्रभु श्रीराम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उसी प्रकार पुष्पक विमान से उतरते हैं जिस प्रकार वह त्रेता युग में उतरे थे। अयोध्या त्रेतायुग में जिस प्रकार प्रफृल्ल्ति व हर्षित हुई थी आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या व उसके आसपास के वातावरण को उसी प्रकार राममय करने की अभूतपूर्व तैयारी चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए हर संभव व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। 22 जनवरी के बाद देश व विदेशों से लाखों की संख्या में रामभक्त अयोध्या पहुंचने वाले हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए और अयोध्या को विश्व स्तर की धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए लागत की विभिन्न अवस्थापना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी दिसंबर माह में उड़ानें भी प्रारंभ हो जायेंगी। वंदेभारत ट्रेन लखनऊ से अयोध्या के बीच चली है और करीब आधा दर्जन अन्य रेल गाड़ियाँ अयोध्या से होकर जाने लगी हैं। अयोध्या से रामेश्वरम तक सीधी रेलगाड़ी चलाई गई है।

अयोध्या का बदलाव दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन को भव्य बनाया जा रहा है। पर्यटन विभाग अयोध्या को जोड़ने वाले सुल्तानपुर, बस्ती, गोंडा, अंबेडकरनगर और रायबरेली हाईवे पर बड़े द्वारों का निर्माण कर रहा है। अयोध्या व आसपास के जिलों व कस्बों में भारी संख्या में होटलों आदि का निर्माण कार्य चल रहा है।

तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं – अयोध्या में बाहर आने वाले तीर्थयात्री केवल अयोध्या मंदिर दर्शन तक ही सीमित न रह जाएं इसलिए तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी कार्य चल रहा है। पंचकोसी, चौदह कोसी तथा चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित धार्मिक स्थलों का भी सुंदरीकरण किया जा रहा है। सरयू नदी में विहार के साथ मंदिरों के दर्शन के लिए क्रूज सेवा और रोमांचक वाटर स्पोर्टस सेवा भी प्रारंभ हो गई है। साथ ही अभी कई और योजनाएं प्रारंभ होने वाली हैं।

भविष्य की दृष्टि से अयोध्या का दिव्य एवं नव्य विकास करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्पवान है। मुख्यमंत्री का दायित्व सँभालने के साथ से ही वे अयोध्या पर विशेष ध यान दे रहे हैं और प्रायः अयोध्या आकर सांधु –संतों का आशीर्वाद के लेने के साथ ही साथ विकास हेतु उनका परामर्श भी लेते हैं । 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी अपने प्रथम कार्यकाल में 46 बार अयोध्या पहुंचे और इस कार्यकाल में भी उनका आगमन निरंतर हो रहा है। वो अयोध्या सम्बन्धी प्रत्येक कार्य पर स्वयं दृष्टि रखते हैं। योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में हर वर्ष दीपोत्सव का आयोजन होने से अयोध्या को एक नयी पहचान मिली है। हर वर्ष दीपों की संख्या गिनीज बुक में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व इस बार भी अयोध्या में अयोजित भव्य दीपोत्सव ने एक नया रिकार्ड बना दिया है और अयोध्या की अनुपम छटा बिखर रही है ।

अयोध्या में विकास की गति को और तीव्र करने के लिए नौ नवंबर 2023 को अयोध्या में रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसने एक नया इतिहास रचा। कैबिनेट बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश सरकार के सभी मंत्री रामलला के दरबार पहुंचे और उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कैबिनेट ने हनुमानगढ़ी में भी हनुमान जी के दर्शन किये और पूजा की। हनुमानगढ़ी में महंत धर्मदास , महंत संतरामदस आदि ने सभी अभिनंदन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अप सभी के आशीर्वाद से अयोध्या विश्व की सबसे सुंदरतम नगरी बनेगी।

अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन– अयोध्या में आयोजित बैठक में अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद व देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन को स्वीकृति दी गयी ।अयोध्या कैबिनेट में शुक तीर्थक्षेत्र विकास परिषद के गठन का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि अयोध्या के समग्र विकास के लिए पहले से ही केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 30,500 करोड़ रुपये की कुल 178 परियोजनाएँ चल रही हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अयोध्या के समग्र विकास के लिए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। यहां आने वाले करोड़घें श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ ही परंपरा और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक नीतियां अब तीर्थ परिषद ही बनायेगा। बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन के भी समग्र विकास के लिए देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद व मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ धाम के विकास के लिए शुक तीर्थ धाम विकास परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। सभी विकास परिषद अपने –अपने क्षेत्रों में किसी भी परियोजना व विकास के प्रस्ताव में परामर्श व मार्गदर्शन करेंगे। बलरामपुर जनपद की अयोध्या से दूरी सड़क मार्ग से मात्र 90 किलोमीटर है यहाँ स्थित माँ पाटेश्वरी धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ है जहां नेपाल के श्रद्धालु भी आते हैं।

अयोध्या को ए आई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) आधारित पहला आत्मनिर्भर शहर बनाने की दिशा में एक पहल

अयोध्या विकास प्राधिकरण और अराहास टेक्नोलॉजीज के बीच सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हुआ करार

संवाददाता

लखनऊ। भारत की प्रसिद्ध जियो स्पासिअल आईटी और एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) कंपनी अराहास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अयोध्या विकास प्राधिकरण के बीच में एक महत्वपूर्ण करार हुआ है। इस रणनीतिक करार का एक मुख्य उद्देश्य अयोध्या को वैदिक आत्मनिर्भर (सस्टेनेबल) शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। इस साझेदारी के अनुसार अयोध्या शहर में स्थानीय प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी फैसले लेने में व्यापक बदलाव लाते हुए वैदिक सिटी सस्टेनेबल इंडेक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। अराहास टेक्नोलॉजीज अपने तकनीकी कौशल, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तथा डाटा बिश्लेषण की सहायता से अयोध्या शहर के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की सहायता करेगी और अयोध्या विकास प्राधिकरण को अयोध्या के अनुशासित विकास के लिए भी रूप रेखा तय करने में सहायता करेगी । दोनों संस्थानों का ये संयुक्त प्रयास अयोध्या शहर को अनूठी चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वित और रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इस पहल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना इसकी सफलता का अभिन्न अंग है। अराहास टेक्नोलॉजीज का एआई–संचालित प्लेटफॉर्म व्यापक डेटासेट के गहन विश्लेषण के लिए एडवांस्ड एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जो अयोध्या के पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता में आंतरिक जानकारी प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म के रियल टाइम मेट्रिक्स विभिन्न निकायों को समय समय पर अयोध्या के विकास की प्रगति की निगरानी करने, मानक निर्धारित करने और अनुकूली, सस्टेनेबल नीतियां बनाने में सहायता करेंगे। ऐसा अनुमान है की करीब 24.70 लाख की आबादी वाले शहर अयोध्या में दिनों दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से अयोध्या में संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और इसके लिए वैदिक सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स इन चुनौतियों के लिए एक संरचित समाधान के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारकों सहित विभिन्न आयामों में स्थिरता का आकलन करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के दृष्टिकोण के तहत इस ऐतिहासिक शहर के विकास के लिए में समकालीन सस्टेनेबल प्रक्रियाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का बेहतर तालमेल होना चाहिए। वैदिक सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स का उद्देश्य शहर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करना, आध्यात्मिक और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देना और नैतिक परंपराओं तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। अयोध्या के नगर आयुक्त और अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विशाल सिंह का कहना है कि''वैदिक सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स अयोध्या के लिए एक दूरदर्शी भविष्य की उद्घोषणा करता है, जो परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पेश करता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण वैदिक सिद्धांतों पर आधारित शहर के विकास की कल्पना करता है, इसके निवासियों की भलाई के लिए कार्य करेगा। अराहास टेक्नोलॉजीज के साथ यह रणनीतिक साझेदारी हमारे दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्लेटफार्म की क्षमताएं, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा समर्थित समन्वित दृष्टिकोण के साथ मिलकर, हमें शहरी चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सशक्त बनाएगी। वैदिक सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स, अयोध्या को ऐसा पहला मंदिर शहर बनाने की अपेक्षा रखता है जो कि एक मॉडल के रूप में अपने एसडीजी सूचकांकों को सक्रिय रूप से रिपोर्ट करेगा।'' इस अवसर पर मौजूद श्री सौरभ राय, सीईओ, अराहास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि ''वैदिक सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स स्थापित करके, अयोध्या न केवल वैश्विक शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, बल्कि भारतीय शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज–यूएलबी) के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारे प्लेटफॉर्म में एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम और जियो–स्पाटियल विश्लेषण का एकीकरण अयोध्या की गतिशीलता की सूक्ष्म समझ सुनिश्चित करता है, चाहे वह पर्यावरणीय, सामाजिक या आर्थिक हो। यह पहल सस्टेनेबल विकास को प्रेरित करने और नीति निर्माताओं को वास्तविक समय और पूर्वानुमानित इनसाइट्स प्रदान करने की हमारी विशेषज्ञता को दर्शाती है। हमारा मानना है कि अयोध्या का वैदिक सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स को अपनाना अन्य शहरों के लिए एक मानक स्थापित करेगा, जो शहरी की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक व्यापक और अनुकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगा।' तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि और सस्टेनेबल सिटी इंडेक्सेज के लिए एक स्ट्रक्चर्ड ट्रैकिंग सिस्टम न होने की दिशा में अयोध्या के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए इस तरह के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैदिक सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स प्लेटफॉर्म इन सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार है, जो अन्य शहरों के सफल मॉडलों के आधार पर अयोध्या की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मूल्यवान आंतरिक जानकारी और अवसर प्रदान करता है।

मेगा सेल्फ हेल्प समूह के स्टाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या जी का सम्मान केनरा बैंक के अंचल प्रमुख और महा प्रबंधक आलोक कुमार अग्रवाल जी ने किया

उ०प्र०राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित मेगा बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम आयोजित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। अत्योदय के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उत्तरप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दिन प्रतिदिन प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र की दीदियो को संगठित करते हुए समावेशी विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उक्त के क्रम में दिनांक 25 नवम्बर 2023 को उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियान्त्रिकी विभाग की अध्यक्षता में उ०प्र०राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित मेगा बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान, लखनऊ के सभागार में किया गया।

मिशन निदेशक द्वारा सभी का स्वागत करते हुए मिशन की प्रमुख घटकों में प्रगति एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को डिजिटल नवाचारों से जोड़ने सम्बन्धित विस्तृत प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए बताया गया कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम में 16 बैंकों द्वारा 44100 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कैश क्रेडिट लिंकेज धनराशि रु०50688 लाख प्रदान किया गया । आज के कार्यक्रम में 13 जनपदों से उपस्थित सभी 1550 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कैश क्रेडिट लिंकेज प्राप्त कर आजीविका के क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री जी ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियान्त्रिकी द्वारा मिशन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए समबोधन में कहा कि माननीय यशश्वी प्रधानमंत्री जी के अन्त्योदय और सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के सतत मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खण्डों मिशन के अंतर्गत 1.21 करोड़ से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की महिलाओ को कुल 8.72 लाख स्वयं सहायता समूहों, 62886 ग्राम संगठनो एवं 3044 संकुल स्तरीय संघो से आच्छादित किया गया है। कुल 620678 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड (931 करोड़ रुपये) 454324 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (4997.57 करोड़ रुपये) के माध्यम से आच्छादित किया जा चुका है एवं 4.45 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 4461 लाख रुपये का ऋण कम व्याज पर सुनिश्चित किया गया है। एक ग्राम पंचायत–एक बीसी सखी के अंतर्गत प्रदेश की सभी 57706 ग्राम पंचायतो में अभी तक 49860 बीसी सखी का प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा चुका है जिसमे से 37068 बीसी सखी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ज्जिसके अंतर्गत बीसी सखी द्वारा अब तक लगभग 51.06

करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया। लखपति महिला कार्यक्रम अंतर्गत अभी तक मिशन के लक्ष्य के सापेक्ष 14: सदस्य लखपति बन गए है।

मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा 1.52 करोड़ मास्क निर्माण, 1.51 करोड़ स्कूल ड्रेस निर्माण, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के माध्यम से 62840 महिला शेयर होल्डर्स के साथ बुंदेलखंड में प्रतिदिन 2.17 लाख किलो ग्राम दुग्ध ा का संग्रह 952 ग्राम पंचायतों से किया जा रहा है। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी की तर्ज पर जनपद–बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र गाजीपुर, चंदौली के 700 ग्रामों में दुग्ध वैल्यू चौन की स्थापना की जा रही है जिसके अंतर्गत 3 वर्ष में 35000 दुग्ध उत्पादों को जोड़ना है एवं परियोजना का बजट 42.23 करोड़ का प्राविधान है। वर्तमान में 14095 महिला सदस्यों द्वारा 468 ग्रामों में प्रतिदिन लगभग 45000 लीटर दुग्ध ा का संग्रहण किया जा रहा है।

महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत अतर्गत पहली दुग्ध उत्पादक कंपनी सामर्थ्य मिल्क प्रोडूसर कंपनी का निर्माण किया गया, जिसका बजट 62.29 करोड़ है जिसमे जनपद–रायबरेली सुल्तानपुर प्रतापगढ़, अयोध्या, कानपूर नगर, अमेठी क 1500 से 75000 महिलाए लाभान्वित होंगी वर्तमान में कंपनी द्वारा 48500 महिला सदस्यों द्वारा 1040 ग्रामों से110000 लीटर दुग्ध का संग्रहण किया जा रहा है। महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत द्वित्तीय कम्पनी का निर्माण श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोडूसर कंपनी का निर्माण किया गया जिसका बजट 34.44 करोड़ स्वीकृत है जिसके अंतर्गत जनपद–गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर एवं देवरिया हेतु 500 ग्रामों की 20000 महिलाये लाभन्वित होगी।

महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत तृतीय कम्पनी का निर्माण श्री सृजनी मिल्क प्रोडूसर कंपनी का निर्माण किया गया जिसका बजट 48.58 करोड़ स्वीकृत है जिसके अंतर्गत जनपद–पीलीभीत, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी शाहजहाँपुर एवं रामपुर हेतु 800 ग्रामों की 32000 महिलाये लाभन्वित होंगी।

वैल्यू चौन अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में झाँसी के 4 विकासखंडो एवं महोबा के 3 विकासखंडो में आगामी 3 वर्षों में 17 ४०६ महिला किसानो को फायदा पहुंचाया जाएगा अभी तक 6920 महिला किसानों को झलकारी बाई महिला प्रोडूसर कंपनी का सदस्य बनाया जा चुका है, इसका बजट 16.36 करोड़ का प्राविधान है।

जनपद बदायूं के 5 विकास खंडो में वैल्यू चौन परियोजना अंतर्गत बदायुनी महिला प्रोडूसर कंपनी का निर्माण किया गया। है आगामी 3 वर्षों में 14275 महिला किसानो को जोड़ने का लक्ष्य है अब तक ४३५१ महिला किसानों को कंपनी का सदस्य बनाया जा चुका है। जरी जरदोजी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के के लिए बदायूं जनपद में जरकता महिला हस्तशिल्प प्रोडूसर कंपनी का निर्माण किया गया है इसका बगत 6.71 करोड़ है अभी तक 250 महिला कारीगरों को कंपनी का सदस्य बनाते हुए प्रशिक्षण का कार्य किया जा चुका है।

772 विकासखंडो के 57264 स्वयं सहायता समूहों द्वारा ड्राई राशन की उपलब्धता 1,52,625 आगनवाडी केन्द्रों पर स्टार्टअप विलेज इंटरप्रयूनेरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत कुल 25560 लघु उधमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के द्वारा स्वः रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रमुख है। 204 विकास खंडो में स्वयं सहायता समूह की दीदियों के नेतृत्व में पुष्टाहार उत्पादन इकाई की स्थापना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। 200 इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है साथ ही 204 प्लांटो को FSSAI लाइसेंस निर्गत किया जा चुका है। 250 करोड़ लागत मूल्य का 37,012 मैट्रिक टन पुटाहार का उत्पादन करते हुए आंगनवाडी केन्द्रों पर पहुंचाया जा चुका है।

महिला समूहों की सदस्यों द्वारा 503 वाहनों का आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत सफल संचालन एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया जाना स्वयं सहायता समूह द्वारा 2305 उचित दर की दुकान का संचालन एवं प्रबंध ान, पंचायती राज विभाग से अभिसरण के माध्यम से ग्राम स्तर पर सभी 826 विकास खंडो में 54218 ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय का प्रबंधन समूह की महिलाओ द्वारा किया जा रहा है।

आज सम्पूर्ण देश में ग्राम्य विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के आपसी बेहतर

समन्वय, सहयोग मार्गदर्शन कुशल नेतृत्व त्वरित निर्णय की क्षमता, विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित अभिसरण से आजीविका संबर्धन की गतिविधि ायों में मिशन महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर चुका है। ग्रामीण विकास में प्रदेश की महिलाओं की भूमिका एवं सहभागी प्रवन्धन की सफल झलक के साथ मिशन आज विकास के हर क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता के साथ अलग पहवान बना चुका है।

कार्यक्रम के अंत में संयुक्त मिशन निदेशक द्वारा बैंकों के प्रतिनिधि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रदेश, जनपद एवं विकास खंड स्तरीय अधि ाकारी समर्पित प्रोफेशनल स्टाफ, राज्य स्तरीय समर्पित प्रोफेशनल स्टाफ आदि को उनके गरिमामयी उपस्थित तथा प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप किये गाए प्रयासों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया।

महिला श्रद्धालु के साथ दुकानदार ने की मारपीट,मारपीट में महिला श्रद्धालु का फटा सर

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार।

अयोध्या धाम को साफ सुथरी एवं सुंदर छवि से निखारने में केंद्र एवं प्रदेश की सरकार दिन–रात काम कर रही है अयोध्या पर्यटन नगरी में विकसित हो पर्यटक अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आवे इसके लिए तन्मयता से योगी की सरकार काम कर रही है हजारों करोड़ रुपयो का बजट अयोध्या की धरती पर केंद्र एवं प्रदेश की सरकार पर्यटकों को लुभाने के लिए लग रही है वही अयोध्या के मनबढ़ छवि के दुकानदार जो गैर जनपदों से आकर व्यापार करते हैं तथा दूर दराज से आए हुए पर्यटकों के साथ हाथापाई एवं मारपीट कर उन्हें लहू लुहान कर देते हैं इसी प्रकार का एक मामला आज हनुमानगढ़ी एवं कनक भवन के बीच रास्ते में पढ़ने वाली पूजा पाठ एवं फोटो की दुकान के मालिकों ने झांसी से आई महिला यात्री अनीता पत्नी अज्ञात के साथ चांद रूपों की बारगेनिंग को लेकर ध ाक्का मुक्की के साथ मारपीट कर मार– मार के महिला यात्री को लहू लुहान कर दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या धाम से गए एक पहर ही बीता है और स्थानीय दुकानदारों के द्वारा इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया।

घटना उसे समय की है जब झांसी से आए एक परिवार कनक भवन दर्शन को जाते समय एक पूजा पाठ सामग्री फोटो की दुकान पर सामान को खरीदने के नियत से रुक गए तथा दुकानदार से बारगेनिंग को लेकर कहां सुनी हुई कहां सुनी ध ीरे–धीरे विवाद का रूप लेती गई तथा दो– तीन दुकानदारों ने एकजुट होकर बाहर से आए महिला यात्री को एकजुट होकर मारने पीटने लगे तथा महिला यात्री के साथ के लोगों को दौड़ा–दौड़ा कर पिटा तथा महिला यात्री के सर से खून निकलने लगा हाथापाई का विवाद इतना बढ गया कि मामला थाना राम जन्मभूमि तक पहुंच गई की थाना राम जन्मभूमि की पुलिस सूचना पाते ही तत्परता से हरकत में आई और दोनों पक्षों को कार्यवाही के लिए थाने में ले गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी प्रकार की एक घटना चंद दिनों पहले भी हो चुकी है अयोध्या के दुकानदारों के इस हरकत से योगी की सरकार पूरी तरीके से शर्मसार हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को कुछ चंद दुकानदारों के कारण धूमिल की जा रही है खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर नहीं प्राप्त हुई थी तथा पुलिस के द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का हुआ आयोजन

सुल्तानपुर– शहर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन ।मुख्य अतिथि सांसद मेनका गांधी,जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह,पूर्व मंत्रीधविध ायक विनोद सिंह,विधायक सीताराम वर्मा,विधायक मोहम्मद ताहिर खान,भाजपा नेता राम चंद मिश्र, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह,ब्लांक प्रमुख शिवकुमार सिंह,ब्लाक प्रमुख कुंवर बहादुर सिंह,जिला पंचायत सदस्य निसार अहमद के साथ भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निर्मित दिव्यांग उपकरण करेंगी वितरित। डीएम कृतिका ज्योत्सना,सीडीओ अंकुर कौशिक एवं एसपी सोमेन वर्मा की मौजूदगी में दिव्यांगों का उपकरण वितरण कार्यक्रम। देश में 20 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम घ्काध आयोजन।

तीसरे जनजातीय गौरव दिवस समारोह के दौरान जागरूकता फैलाने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), कुम्हरावां पहुंची सीएसआईआर-सीडीआरआई की टीम

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में, सीएसआईआर–सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीडीआरआई) लखनऊ ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, कुम्हरावां, बख्शी का तालाब, लखनऊ में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

सीडीआरआई की एक टीम ने स्कूल में जाकर कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया। जिज्ञासा समन्वयक डॉ. संजीव यादव और प्रधान वैज्ञानिक डॉ. श्रीपति आर कुलकर्णी के नेतृत्व वाली टीम के साथ–साथ संस्थान के चार अन्य स्टाफ सदस्यों का उद्देश्य वंचित ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को अपने जीवन में प्रगति करने के लिए प्रेरित करना था।

डॉ. संजीव यादव ने बालिकाओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से बताया कि, देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पिछड़े आदिवासी समुदाय से होने के बावजूद अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत से सर्वोच्च पद तक पहुंचीं हैं। उन्होंने भारत के माननीय राष्ट्रपति और अन्य सफल महिला नेताओं के अनुकरणीय जीवन से प्रेरणा लेते हुए चुनौतियों पर काबू पाने और उत्कृष्टता हासिल करने के महत्व पर जोर दिया।

डॉ. संजीव ने बालिकाओं को अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, साथ ही सीडीआरआई में विकसित दवाओं के बारे में जानकारी भी साझा की। स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर देने का उद्देश्य वंचित ग्रामीण बालिकाओं को ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है जो उनके समग्र कल्याण में सहायक सिद्ध होगा।

इसके अलावा, डॉ. श्रीपति कुलकर्णी ने बच्चों के बीच शिक्षा और करियर में उन्नति के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने न केवल उन्हें बौद्धिक रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित किया बल्कि उनको शैक्षिक और व्यावसायिक यात्राओं में सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने का भी प्रयास किया। रवीद्र, नितिन और अमर ने प्रतिभागियों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की और विजेताओं को पुरस्कार मिला तथा अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना उपहार मिले। केजीबीवी की प्रध ाानाचार्या ममता सिंह ने बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए टीम सीडीआरआई द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की तथा अन्य शिक्षक एवं कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

पाली पुलिस ने शांति भंग की आशंका में 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कानूनी रूप से किया पाबंद

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–हरदोई' माननीय मानवाधि ाकार आयोग व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का पालन करने एवं थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने व किसी संज्ञेय अपराध को रोकने हेतु शांति भंग की आशंका में पाली पुलिस ने 12 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मुचलके से पाबंद करते हुए विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पाली पुलिस ने ग्राम महमदापुर से 09 व ग्राम निजामपुर से 03 लोगों समेत 12 को पाबंद किया है। इनमें रामनरेश (58) व रामकिशुन (56) पुत्र रामप्रसाद, रिखिराज (32) व मनवीर(25) पुत्र रामनरेश, योगेन्द्र (24) पुत्र रामकिशुन,विमलेश (28) पुत्र रामपाल,मूलचंद्र (45) पुत्र सियाराम,कालिका (42) पुत्र लल्लू, वकील खां (45) पुत्र नन्हें खां उक्त निवासी ग्राम महमदापुर थाना पाली व नेमिश शर्मा (19) पुत्र सूरजपाल शर्मा, रोहित कुशवाहा (20) पुत्र सतीश कुमार, सूरज (26) पुत्र पंचम निवासी ग्राम निजामपुर थाना पाली जनपद हरदोई शामिल हैं। प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार राय ने बताया कि पाली पुलिस ने शांति भंग की आशंका व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से उपरोक्त नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मुचलके से पाबंद कर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया।

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और जिलाधिकारी ने कोलोसियम 2023 का किया उद्घाटन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एण्ड कॉलेजेज के संस्थापक एवं महाप्रबंधक डॉ. एस.पी. सिंह के नेतृत्व में 6वीं इंटर स्कूल स्टेट एथलेटिक चौंपियनशिप कोलोसियम 2023 का शुभारम्भ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम में किया गया । चौंपियनशिप का उदघाटन उपेन्द्र कुमार अग्रवाल (आईपीएस), संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और सूर्यपाल गंगवार (आईएएस), जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा, कान्ति सिंह (पूर्व एमएलसी), निदेशक नेहा सिंह, उप निदेशक मीना टांगड़ी, प्रधानाचार्या भारती गोसाईं, अनीता चौधरी, मीना तिवारी, सुनंदा माथुर, ज्ञानेंद्र कुमार, डॉ. रितु सिंह, वी.के. शर्मा (सी आई), योगेश कुमार गुप्ता (परीक्षा नियंत्रक), शिक्षकों और मीडियाकर्मियों की उपस्थिति में किया गया । संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं जिलाधिकारी दोनों ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें संबोधित करते हुए आत्मविश्वास, टीम वर्क और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने पर जोर दिया । उद्घाटन समारोह के बाद तीन दिन तक जलती रहने वाली मशाल को प्रज्वलित किया गया द्य कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागियों के अपने ध्वजवाहकों और स्कूल बैंड के साथ मार्च पास्ट से हुई । बैक पाइप बैंड ने मधुर धुन बजाई जिससे प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ गया। इस आयोजन में प्रदेश के 49 विद्यालय और 1500 से अधि ाक छात्र भाग ले रहे हैं । पुरस्कार वितरण मुद्रिका पाठक (उप निदेशक खेल, खेल निदेशालय, लखनऊ) द्वारा किया गया । इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ओलिंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष टी पी हवेलिया, आत्या पात्या फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव युजिन पाल एवं राजन सिंह उपस्थित रहें।

जिले के टॉप 10 अपराधियों के दोष सिद्ध कराए

संवाददाता

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के सभी डीएम,एसपी और पुलिस कमिश्नर को टॉप 10 अपराधियों को दो सिद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लेटर में लिखा कि बीते 2 वर्षों से टॉप 10 अपराधियों को लेकर जो समीक्षा बैठक की गई। ऐसे में अभियोजन की कार्यवाही में लापरवाही मिली है। अपर मुख्य सचिव गृह ने प्रदेश के 46 जिलों में स्थित संतोषजनक ना होने पर नाराजगी जताई है, तत्काल स्थितियां सुधारे जाने के लिए निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद के द्वारा दिए गए।

बाल विद्या मन्दिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, चारबाग में हीरक जयंती उत्सव मनाया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। बाल विद्या मन्दिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, चारबाग के ष्हीरक जयंतीष् उत्सव के गौरवशाली अवसर पर दिनाँक 24.11.2023 को विद्यालय के प्रांगण में बड़ी धूम धाम रही। इस अवसर की गरिमा को और अधिक गौरवान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मा० शिव प्रताप शुक्ला जी, मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मन्त्री उ०प्र० एवं पूर्व सांसद मा० कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने की। कार्यक्रम के संयोजक डॉ० ओम प्रकाश अग्रवाल जी माननीय सदस्य मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी प्रशासन परिषद रहे।

इस अवसर पर मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के प्रशासन परिषद के मा० पदाधिकारीगण उपाध्यक्ष श्री केशव प्रसाद जी, मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के महामंत्री ध बाल विद्या मंदिर स्कूल के प्रबन्धक श्री राजेश सिंह जी, संयुक्त मंत्री श्री प्रताप सिंह जंगलिया जी व डॉ० ऊषा चौधरी जी (सदस्य, मो०मेमो०सो०) श्री रत्नेश गुप्ता जी, श्री शैलेश त्रिपाठी जी सहित सभी सदस्यगण और माननीय (डॉ०) अशोक बाजपेयी जी (पूर्व मंत्री, उ०प्र०ध्सांसद, राज्यसभा एवं अध्यक्ष भारत सेवा संस्थान), माननीय आर० सी० त्रिपाठी (पूर्व आई० ए० एस०) एवं सभी सदस्यगण तथा विद्यालय के प्राचार्य डॉ० आर० के० पाण्डेय जी व प्रदेश के अनेक गणमान्य नेता व अधि ाकारीगण तथा विद्यालय के सम्मानित अभिभावकगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के आरम्भ में मो०मेमो०सो० के महामंत्री ध बा०वि०म० के प्रबन्धक श्री राजेश सिंह जी द्वारा मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित एवं मंचस्थ अन्य विशिष्ट अतिथियों को प्राचार्य डॉ० आर० के० पाण्डेय द्वारा पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिह्न देकर गर्मजोशी से सम्मानित स्वागत किया गया। तत्पश्चात् छात्रों द्वारा गणेश वन्दना एवं स्वागत गीत की सुन्दर प्रस्तुति की गई।

इस पावन अवसर पर माननीय महामहिम द्वारा विद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय चन्द्रभानु गुप्त जी की श्प्रतिमा का अनावरण एवं विद्यालय के श्स्पोटर्स हब का शिलान्यासश एवं श्साइबर विधि पुस्तकश द्वारा लिखित डॉ० पियूष कुमार त्रिवेदी एवं श्री एम०एच० जैदी (साइबर क्राइम लीगल एक्सपर्ट) का का विमोचन भी किया गया।

विद्यालय के ष्हीरक जयंतीष् के इस गौरवशाली अवसर पर विशिष्ट पूर्व छात्रों को सम्मानित करने का भी कार्य किया गया।

प्रस्थान आश्रम पठानकोट पंजाब की संचालिका माता जी सुमति मित्तल कल भगवान की प्यारी हो गईं

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। विनोबा विचार प्रवाह के सूत्रधार रमेश भइया ने बताया कि आचार्य विनोबा ने भूदान यात्रा के दौरान पांच आश्रम जो देश के अलग अलग कोने में अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए स्थापित किए उनमें पहला समन्वय आश्रम बोध ागया बिहार , दूसरा विसर्जन आश्रम इंदौर मध्यप्रदेश, तीसरा प्रस्थान आश्रम पठानकोट पंजाब , चौथा विश्वनीडम बंगलौर कर्नाटक, और पांचवा मैत्री आश्रम नार्थ लखीमपुर आसाम हैं। 'इसमें से पाकिस्तान की सीमा पर पठानकोट में स्थापित आश्रम सत्यम भाई यशपाल मित्तल जी के बाद आदरणीय माता जी श्रीमती सुमति मित्तल जी संचालक के रूप में देखती थीं।' मेरा राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य संदेश पदयात्रा के अलावा जब भी धर्मशाला आदरणीय सामदोंग रिमपोछे जी के यहां जाना होता था तो वही जाकर फिर आगे जाना होता था। इस दृष्टि से कई बार वहां जाना हुआ। विनोबा 125 में प्रस्थान आश्रम का प्रतिनिधि ात्व करने टीम भी ब्रह्मविद्या मंदिर पवनार वर्धा आई थी

अभी वहां से गुप्ता जी आदि के द्वारा दुखद संदेश मिला है।

'अत्यन्त दुःखी ह्रदय से कहना है कि हमारी पूज्य माँ श्रीमती सुमति मित्तल धर्मपत्नी श्री यशपाल मित्तल जी, संचालिका प्रस्थान आश्रम,' 'पठानकोट, कल 24 नवंबर को श्री चरणों में विलीन हो गयी हैं।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित ।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।